खंड ७

बिहार विधायिका सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि २८ नवम्बर, १९४९।

सत्यमेव जयते

६—६

अर्थ

का

२१

का

...हूं में सत्ता की कमना.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ... ३१

...बिल १९४९ (१९४९ की वि...यक

प्रस्ताव पर बहस जारी।)

[मूल्य—६ आ०]

कृषि सम्बन्धी रिन ।

१३० । श्री बृजलाल दुकानिया : क्या माननीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या यह सही है कि संथाल परगना जिलान्तर्गत साहेबगंज से प्रकाशित एक हिन्दी सप्ताहिक के २८ जून, १९४८ वाले अंक में प्रकाशित 'सरकार को कृषि सम्बन्धी रिन देना चाहिए; शीर्षक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि गोडा सबडिवीजन के मनिहारी तालुका और पास वर्ती क्षेत्रों में पिछले साल धान की उपज बहुत कम हुई जिसके फलस्वरूप सब धान की खपत स्थानीय किसानों के भोजन में ही हो गई है और फिर से रोपने के लिए न उनके पास धान है न बीज खरीदने का साधन;

(ग) अगर खंड (ख) का उत्तर 'हां' में है तो डिप्टी कमिश्नर द्वारा क्या कर्रवाई की गई थी और अगर नहीं तो क्यों ?

माननीय डा० सैयद महमूद :

(क) उत्तर 'हां' में है ।
(ख) उत्तर 'हां' में है ।

(ग) सथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर ने ११,५५० रुपए रिण के रूप में गोडा सबडिवीजन में दिया । और मनिहारी तालुका इससे अपवाद नहीं । धान और चावल भी बांटे गए । धान के खेतों में धान रोपने का कार्य संतोषजनक रूप से हुआ है । कोई भी धान का खेत परती नहीं छोड़ा गया ।

पाकुड़ और राजमहल सबडिवीजन में क्रेडिट ऐग्रीकोल का डिपो ।

१३१ । श्री बृजलाल दोकानिया : क्या माननीय मंत्री, विकास विभाग के, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सरकार की ओर से संथाल परगना जिला के पाकुड़ और राजमहल सबडिवीजनल क्रेडिट ऐग्रीकोल के डिपो राजमहल खास, साहेबगंज, बरहरवा, पाकुड़ खास और महेशपुर, वगैरह, में खोले गए हैं यदि हां तो क्या सरकार का उद्देश्य इन डिपुओं द्वारा पूरा हो रहा है ;

(ख) क्या यह बात सही है कि लगभग तीन साल से उपरोक्त डिपुओं का निर्माण किया गया पर आजतक उन डिपुओं में सिवाय खाद के और दूसरी कोई किस्म की वस्तु किसानों के हित के लिए नहीं रखी गई है ;

(ग) क्या यह बात सही है कि लोहे का औजार (एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट) किसानों को इन डिपुओं से नहीं मिलने की वजह से इस इलाके में ग्रो मोर फूड में जो तरक्की होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है ?

माननीय डा० सैयद महमूद :

(क) यह सही नहीं है कि प्रश्न में दिए गए स्थानों में सरकार ने कोई डिपु खोला है । लेकिन क्रेडिट ऐग्रीकोल स्कीम के अन्तर्गत प्रान्तीय सहकारी बैंक ने इन डिपुओं को खोला है और ऐसा अनुमान किया जाता है कि ऐग्रिकोल स्कीम में दिए गए प्रयोजनो की पूर्त्ति हो रही है ।

(ख) प्रत्येक के सामने दी गई तिथि से डिपुओं में काम हो रहा है :—

(१) बरहरवां—१जून, १९४८ ।

(२) पाकुर—१५ जुलाई, १९४८ ।
(३) साहिबगंज—१६ जुलाई, १९४६ ।
(४) महेशपुर—१६ दिसम्बर, १९४६ ।
(५) राजमहल—२ जुलाई, १९४६ ।

खाद के अलावा कृषि विभाग द्वारा बीज भी मिलने पर वितरण किया जाता है ।

(ग) कृषि उपकरणों का बितरण अभी तक डिपुओं द्वारा नहीं होता ।

श्री बृजलाल दोकानिया : (क) से सरकार अनुमान करती है, इससे क्या मतलब है ?

श्री वीर चन्द्र पटेल : यह साइकोलाजी का सवाल है या क्रेडिट एग्रीकोल स्कीम प्रान्तीय सरकारी बैंक के अन्दर है और सरकार ऐसा समझती है या अनुमान करती है कि ऐग्रिकोल स्कीम में दिए गए प्रयोजनों की पूर्ति हो रही है ।

माननीय प्रमुख : जानकारी की बात उत्तर में कहनी चाहिये ।

श्री वीर चन्द्र पटेल : बहुत से सवाल ऐसे रहते हैं कि निश्चित जानकारी के रूप में जवाब देना असम्भव नहीं होता है। चूंकि मेम्बरों को अधिक से अधिक प्रकाश मिल सके इसलिये जवाब का क्षेत्र (scope) ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर देने की कोशिश की जाती है। आगे हम लोग इसका ख्याल रखेंगे कि अनुमान से जहां तक हो कम जवाब दिया जाय।

श्री बृजलाल दोकानिया : खाद के अलावे कृषि विभाग बीज दे तो क्रेडिट एग्रीकोल को वितरण करने में कौनसी कठिनाई है?

श्री वीर चन्द्र पटेल : सरकार डिस्टिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिस के जरिये इस काम को अच्छी तरह से कर रही है इसलिये ऐग्रीकोल के जरिये नहीं करती है।

श्री बृजलाल दोकानिया : आप ने जवाब में कहा है कि ऐग्रीकोल डिपो को बीज बांटने के लिये नहीं दिया जाता है। सरकार के सामने कौन सी कठिनाई है जिसकी वजह से ऐग्रीकोल डिपो को बीज नहीं दिया जाता है?

श्री वीर चन्द्र पटेल : इसलिये नही दिया जाता है कि वह सरकारी संस्था नहीं है। वह तो प्राविंशियल को आपरेटिव बैंक के अन्दर है। खाद बांटने का काम वह सहूलियत से कर लेता है। इसलिये खाद बांटने के लिये दिया जाता है मगर बीज नहीं दिया जाता है क्योंकि सरकार की यही नीति अभी तक है।

श्री बृजलाल दोकानिया : जब आप बीज उसको नहीं देते हैं तो क्या यह कागजी जमाखर्च है या सचमुच में ... .

माननीय प्रमुख : शांति-शांति।

श्री जगन्नाथ सिंह : क्या सरकार को पता है कि कृषि विभाग ने बीज वितरण का काम छोड़ दिया है और सरकार ने जो जवाब दिया है वह गलत है।

श्री वीर चन्द्र पटेल : बिल्कुल सही है।

माननीय सदस्य को खबर नहीं है।

श्री जगन्नाथ सिंह : कृषि उपकरण का किसके जरिये वितरण होता है?

श्री वीर चन्द्र पटेल : कृषि उपकरण यानी खुरपी और कुदाल तो बांटी नहीं जाती है।

श्री जगन्नाथ सिंह : हल और फाल इत्यादि किसानों तक पहुंचाने की कोई स्कीम है या नहीं ?

श्री वीर चन्द्र पटेल : सरकार इस पर विचार कर रही है। अब तक होता यह था कि डाईरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज की तरफ से कृषि औजार बनाने के कारखानों को लोहा दिया जाता था लेकिन अब इस प्रश्न पर फिर से विचार हो रहा है कि कृषि औजार बनाने के कारखानों को किस तरह लोहा दिया जाय, या इन्डस्ट्रीज विभाग इसको करे या कृषि विभाग करे ।

श्री नन्द किशोर नारायण लाल : क्या यह सही है कि खाद का काम कृषि विभाग से लेकर क्रेडिट ऐग्रीकोल को दिया गया है ।

श्री वीर चन्द्र पटेल : इसका जवाब पांच बार दिया जा चुका है ।

श्री रास बिहारी लाल : डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसों में अभी भी हल कुदाल की बिक्री होती है ।

श्री वीर चन्द्र पटेल : लड़ाई के जमाने में ये सब सामान किसी जिलो में बांटे गये थे । वही सामान किसी जगह बच गया होगा जो अब भी बिक रहा होगा वर्ना विभाग की तरफ से नहीं बिकता है।

श्री शक्ति कुमार : कहा गया है कि हल फाल इत्यादि दिया जाता है तो क्या सरकार जहानाबाद —

माननीय प्रमुख : शान्ति-शान्ति । यह सवाल नहीं उठता है ।

श्री वीर चन्द्र पटेल : सरकार की तरफ से कहा गया है कि नहीं बढ़ता है ।

प्रश्न संख्या ११४ ।

श्री फूलन सिंह : प्रमुख महोदय, मेरे सवाल न० ११४ का जवाब आज मिलेगा या नहीं ?

माननीय प्रमुख : आज कल जिस रीति से काम चलता है उसके अनुसार माननीय मंत्रियों के लिए एक एक दिन निर्धारित हो जाता है। इसलिये इस प्रश्न का जवाब उस दिन मिलेगा जिस दिन इस प्रश्न से संबंधित विभाग के मंत्री अपने प्रश्नों का जवाब देंगे ।